DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 14 मई 2022 TED-

क्राइम कंट्रोल पर RWAs से मदद लेगी पुलिस, बनाई एडवाइजरी

■ विशेष संवाददाता, द्वारका

'अनजान बाइकर्स से रहें चौकन्ना... स्नैचिंग से बचें'

- द्वारका की सोसायटियों के लिए पुलिस ने जारी की खास एडवाइजरी
- डीसीपी की ओर से जारी एडवाइजरी में सभी गाड़ियों में जीपीएस लगवाने की सलाह भी दी गई है

द्वारका में बढ़ रही स्नैचिंग की वारदातों को लेकर अब पुलिस ने विभिन्न सोसायटियों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें सोसायटियों को कई तरह की सलाह दी गई है। पुलिस की यह एडवाइजरी एसीपी मदन लाल मीणा की तरफ से जारी की गई है। इसमें लोगों को सोसायटियों के आसपास घूम रहे अनजान बाइकरों पर नजर रखने, उनकी सूचना पुलिस को देने, गाड़ियों व स्कूटरों में जीपीएस लगवाने की सलाह भी शामिल है।

पार्कों पर दी गई सलाह के बाद लोग पार्कों में लाइट न होने और रात के समय असामाजिक तत्वों के शराब पीने की कई शिकायतें अब पुलिस तक पहुंचा रहे हैं। जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सुबह शाम पार्कों में घूमते समय, स्कूल के लिए अपने बच्चों को ले जाते या घर लाते समय, अपार्टमेंट के गेट के बाहर स्कूल बस में बिठाते हुए सतर्क रहें। इस दौरान ध्यान रखें कि यदि किसी बाइक या स्कूटर पर सवार दो लड़के या कोई पैदल चलने वाला भी आपका पीछा कर रहा है या आपके पास खड़ा है तो सचेत हो जाएं।

ऐसे लोग आपके फोन, चेन आदि झपट सकते हैं। ऐसे लोगों के नजर आने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। वहीं द्वारका डीसीपी की तरफ से द्वारका में सुरक्षा आपके द्वार योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत पुलिस भी कई तरह के कदम उठा रही है।

इस नोटिस के बाद सोसायटियों ने सूचना पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। द्वारका सेक्टर-9 फेडरेशन ऑफ सोसायटी एंड आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष डॉक्टर खेम सिंह भाटी ने बताया कि डीडीए पार्क नंबर 3 सेक्टर-9 में अंधेरा होने के बाद कई युवक आकर शराब पीते हैं। इसकी शिकायत पहले भी की गई है, लेकिन हल नहीं हुआ। इसी तरह की शिकायतें कुछ अन्य आरडब्ल्यूए और सोसायटियों ने भी की है।

पुलिस की सलाह, ऐसा करने से कम होगा क्राइम

- सोसायटी के मैन गेट के दोनों तरफ कैमरा लगवाना
- सभी लोग अपनी गाड़ियों, जिसमें कारें, स्कूटर और बाइक सभी शामिल, में जीपीएस लगवाएंगे
- बाहर जाते समय आरडब्ल्यूए को बंद फ्लैट की जानकारी देना
- सोसायटी में कैमरे लगवाकर अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की मदद
- नए किरायेदारों और सोसायटियों में आ रहे हेल्परों की सूचना पुलिस को देंगे और उनकी वेरिफिकेशन भी करवाएंगे
- सोसायटी के आसपास किसी संदिग्ध के घूमने की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाएं
- पार्कों के आसपास व पार्क में संदिग्धों व शराब पीने वालों की जानकारी पुलिस को दें

व्यापारियों के साथ डीडीए उपाध्यक्ष की मुलाकात

■ वि, नई दिल्ली : एनडीएमसी उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने 9 मई को डीडीए उपाध्यक्ष से उनके डीडीए कार्यालय, विकास सदन, नई दिल्ली में ग्रीन पार्क मार्केट असोसिएशन के दुकानदारों और व्यापारियों के साथ दुकानों की सीलिंग से जुड़े मुद्दे पर मुलाकात की। वहीं अखिल भारतीय दिल्ली विकास प्राधिकरण इंजिनियर्स असोसिएशन के पदाधिकारी परम यादव ने भी उपाध्यक्ष-डीडीए से मुलाकात की।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 14 मई 2022 ED

सिसोदिया ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कार्रवाई रोकने की मांग की

दिल्ली को तबाह करने के लिए बीजेपी ने बनाया वसूली का प्लानः सिसोदिया

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

उपमुख्यमंत्री ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली में 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर बीजेपी शासित एमसीडी द्वारा दिल्ली को बर्बाद करने से रोकने को कहा है। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में बुलडोजर से वसूली का बड़ा प्लान बनाया है और बुलडोजर से वसूली के लालच के कारण पूरी दिल्ली को तहस-नहस करने में लगी हुई है।

सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। आज बीजेपी पूरी दिल्ली में बुलडोजर लेकर घूम रही है, क्योंकि उसने दिल्ली के 63 लाख लोगों को बेघर करने का पूरा प्लान बना लिया है। कच्ची कॉलोनियों और झुग्गियों में बने घरों में 60 लाख लोग रहते हैं और बीजेपी का इन सबको तोड़ने का प्लान है। पहले तो बीजेपी नेताओं ने पैसे लेकर इन्हें अवैध तरीके से बसाया और फिर उन्हें तोड़ रही है और इसके साथ-साथ डीडीए कॉलोनी में बालकनी-कमरे बनाने या घरों में छोटे-मोटे ऑपरेशन करने वाले 3 लाख लोगों के मकान भी तोड़ेगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी दिल्ली की 70 प्रतिशत आबादी के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर करने की तैयारी में है। ये दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में अराजकता को सबसे बड़ी तबाही होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एमसीडी में कार्यकाल पूरा हो चुका है फिर भी वो वसूली के लिए बुलडोजर लेकर घूम रही है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी के बुलडोजर से वसूली के इस घटिया राजनीति का विरोध करती है। आज बीजेपी की वजह से पूरी दिल्ली की जनता पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का 1-1 कार्यकर्ता और दिल्ली सरकार लोगों के साथ खड़ी है, चाहे हमें जेल जाना पड़े लेकिन बुलडोजर को रोककर जनता को तबाह होने से बचाएंगे।

सिसोदिया ने चिट्ठी के माध्यम से अमित शाह से कहा कि इन लोगों की जवाबदेही तय करें, जिन्होंने पैसे लेकर 10 साल में ये निर्माण होने दिए।

बिना वजह डरा रहे हैं डिप्टी सीएम : आदेश

आदेश गुप्ता, नेता

■ बिस, नई दिल्ली : बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी सिसोदिया और आम आदमी पार्टी पर अतिक्रमण विरोधी मुहिम को धार्मिक रंग देकर लोगों को डराने का आरोप लगाया। सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बयान जारी कर आदेश गुप्ता ने कहा कि जबसे रोहिंग्या-बांग्लादेशियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चलाया जा रहा है, तबसे दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दर्द हो रहा है। इस कार्रवाई के बाद शब्द वह मीडिया के सामने आकर दिल्ली की जनता के अंदर डर फैला कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि अवैध रोहिंग्या-बांग्लादेशी, जो पार्टी का वोट बैंक है, उनका दिल्ली से हटना तय है। आदेश गुप्ता ने कहा कि अतिक्रमण को धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है, लेकिन आप और उसके नेता इसे मजहब से जोड़कर लोगों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सिसोदिया को इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत देते हुए कहा कि आप नेता अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण देना बंद करें।

सिसोदिया पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, MAY 14, 2022

'Compensatory plantation norms will not be relaxed'

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Environment minister Gopal Rai on Friday said they would not reduce the number of saplings under compensatory plantation from 10 to two. Delhi Development Authority had recently requested Delhi government to relax the norm of planting 10 saplings for each tree being cut down to two.

In response to DDA's letter, Rai said, "Describing the scarcity of land, DDA has requested to revise the compensatory plantation from 1:10 to 1:2. The forest department has been directed to issue an order directing DDA to submit a detailed report on the available land to them. In anticipation of a potential land constraint and to increase green cover in Delhi, the department has formed a nine-member green cover development committee. This committee will work to increase green space based on land availability."

The minister said the government's policy of planting 10 trees for every tree felled would continue. "Considering Delhi's environment condition, we are rejecting DDA's proposal as we cannot compromise with it," he further stated.

The nine-member committee will have two representatives from PWD and one each from CPWD, DDA, forest department, corporation, School of Planning and Architecture, Delhi Urban Art Commission and Indian Agricultural Research Institute. It will suggest alternatives to overcome land shortage and look for options like utilising space on rooftops of government buildings and vertical greening.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
SATURDAY
MAY 14, 2022

NAME OF NEWSPAPERS- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 14 मई 2022 TED-

Hindustan Times

PANEL TO REVIEW GREEN COVER IN CAPITAL, SAYS RAI

NEW DELHI: The Delhi government on Friday constituted a nine-member green cover development committee to enrich and increase Delhi's green cover and said it will also engage the Forest Research Institute in Dehradun to independently audit the tree transplantation done by all departments to monitor progress on ground.

Departments that fail to submit reports of their tree transplantation work so far will not be granted construction clearances anymore, environment minister Gopal Rai said on Friday.

In response to a Delhi Development Authority (DDA) letter, seeking to revise the tree transplantation policy for compensatory plantation — from 10 saplings for every tree cut to two saplings for each tree felled — citing paucity of land, Rai said the forest department has been directed to seek a detailed report from the DDA on the land available with it.

The government will blacklist any empanelled agency that does not perform tree transplantation work optimally. The Forest Research Institute Dehradun will also audit the tree transplantation exercise, Rai said. HTC

वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को लेकर सरकार सख्त, की समीक्षा बैठक

9 सदस्यीय ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी का किया गठन

■ विस, नई दिल्ली : वृक्ष प्रत्यारोपण (ट्री ट्रांसप्लांटेशन) की नीति को लेकर शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वन विभाग, एमसीडी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सीपीडब्ल्यूडी, एनसीआरटीसी, पीजीसीआइएल, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड आदि विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पहले विकास कार्य के लिए पेड़ों को काटा जाता था और उनकी जगह पर नए पौधे लगाए जाते थे। जो नए पौधे लगाए जाते हैं, उनको विकसित होने में काफी समय लगता था, इसलिए सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण नीति बनाई, ताकि जो पेड़ पौधे ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, उनको ट्रांसप्लांट किया जाए सके।

मंत्री ने कहा कि पिछले साल में जिन एजेंसियों ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन के लिए विभाग से अनुमति ली थी, उसे लेकर शुक्रवार को संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक के दौरान आई रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया है की विभिन्न विभागों और एजेंसियों के वृक्ष प्रत्यारोपण को लेकर अलग अलग सर्वाइवल रेट है, जिसमें वृक्षों का औसतन सर्वाइवल रेट 50 से 55 प्रतिशत पाया गया है। साथ ही कई एजेंसियों और विभागों के संतोषजनक परिणाम नहीं होने के कारण विभागों द्वारा किए गए ट्री ट्रांसप्लांटेशन का ऑडिट अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट, देहरादून करेगी।

गोपाल राय ने कहा जो भी एजेंसी ट्री-ट्रांसप्लांटेशन से संबंधित कार्य को बेहतर रूप से नहीं करेगी, उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

पर्यावरण मंत्री ने डीडीए की तरफ से आए पत्र के बारे में जवाब देते हुए बताया कि डीडीए ने जमीन की कमी बताते हुए प्रस्ताव दिया कि एक काटे गए पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने की जगह केवल 2 पेड़ लगाने का नियम बनाया जाए। इस प्रस्ताव को लेकर सबसे पहले वन विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह डीडीए को जमीन के संदर्भ में डिटेल रिपोर्ट जमा करने के लिए आदेश जारी करे, जिससे कि डीडीए के पास उपलब्ध जमीन का पूरा ब्यौरा विभाग को मिल सके। हरित क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर 9 सदस्यीय ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है।

दिल्ली सचिवालय में शुक्रवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक

> जिन विभागों ने वृक्ष प्रत्यारोपण से संबंधित रिपोर्ट नहीं सौंपी, उन विभाग से संबंधित फाइलों को अनुमति नहीं मिलेगी —गोपाल राय, पर्यावरण मंत्री

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS हिन्दुस्तान नई दिल्ली, शनिवार, 14 मई 2022 DATED

उपमुख्यमंत्री ने भाजपा पर बुलडोजर से वसूली का आरोप लगाया, आदेश गुप्ता ने कहा-अभियान को मजहबी रंग दिया जा रहा

राजधानी में बुलडोजर पर छिड़ा सियासी संग्राम

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली में बुलडोजर पर सियासत तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भाजपा बुलडोजर से वसूली कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कार्रवाई को रुकवाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उधर, भाजपा ने कहा कि जब से निगम ने रोहिंग्या-बांग्लादेशियों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाना शुरू किया है तब से आप को परेशानी हो रही।

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली भाजपा ने नगर निगम के साथ मिलकर दिल्ली को तबाह करने की योजना बनाई है। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों और झुग्गियों में बने घरों में 63 लाख लोग रहते हैं। भाजपा की इन सबको तोड़ने की योजना है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले निगम अधिकारियों और भाजपा नेताओं की मिलीभगत से इसे अवैध ढंग से बनाया गया है। अब बुलडोजर चलाकर तोड़ा जा रहा है। साथ ही डीडीए कॉलोनी में बालकनी-छज्जा बनाने या घरों में छोटे-मोटे बदलाव करने वाले तीन लाख लोगों के मकानों को भी तोड़ने की तैयारी है।

गृह मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि अगर यह हुआ तो दिल्ली के 63 लाख घरों में तोड़फोड़ की जाएगी। पत्र में आगे लिखा गया है कि अगर यह अवैध था तो भाजपा शासित निगम ने इसे बनने क्यों दिया। पहले 15 वर्षों तक यह अवैध निर्माण होने दिए गए। अब उन्हीं लोगों के घरों को तोड़ने पर आमादा है। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इसे समय रहते रोका जाए, नहीं तो दिल्ली में तबाही मच जाएगी।

हम कार्रवाई का विरोध करते हैं : अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम कार्रवाई का विरोध करते हैं।

केजरीवाल ने आप विधायकों की बुलाई बैठक

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आप विधायकों की बैठक बुलाई है। पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पहले ही कह चुके हैं कि आप विधायक बुलडोजर का विरोध करने के लिए जनता के साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली में अगले कुछ महीनों में नगर निगम चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी को कोई नुकसान न हो, पार्टी यह जानकर बुलडोजर राजनीति पर आगे की रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद विधायकों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

भाजपा का पलटवार

पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि अवैध अतिक्रमण को धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है, लेकिन आप नेता इसे मजहब से जोड़कर लोगों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आदेश गुप्ता ने कहा कि रोहिंग्या-बांग्लादेशी दिल्ली में दंगे करते हैं, अपराध करते हैं आप नेताओं को दिल्ली के गरीबों की चिंता नहीं है।

दक्षिण निगम के आश्रम में शुक्रवार को निगम दस्ते ने कार्रवाई करते हुए सड़क पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। आश्रम में 1400 मीटर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया और 23 सामान सहित दो वाहनों को जब्त किया।

75 झुग्गियां और 15 कमरे ढहाये गए

13 सौ मीटर का इलाका अतिक्रमण मुक्त किया

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 14 मई, 2022

दिल्ली जागरण

पार्कों में बन रहीं मस्जिदें, लोग नाराज

बच्चों के खेलने को भी जगह नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान से बंधी आस

सोनू राणा • बाहरी दिल्ली

बवाना जेजे कालोनी के पार्कों में धड़ल्ले से मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से बच्चों के खेलने व बुजुर्गों के टहलने की जगह खत्म होती जा रही है। सरकारी जमीन पर किए जा रहे धार्मिक स्थलों के निर्माण को लेकर स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। अब जिस तरह से नगर निगम ने दिल्ली में अतिक्रमण व अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान छेड़ा है, ऐसे में लोग आस लगाकर बैठे हैं कि बवाना जेजे कालोनी के पार्कों से भी जल्द अतिक्रमण हटाया जाएगा।

विडंबना है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर इस तरह के अतिक्रमण व अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले वह झुग्गी डालकर छोटा सा धार्मिक स्थल बनाते हैं और फिर धीरे-धीरे उसे बड़ा रूप दे दिया जाता है। जैसे-जैसे चंदा इकट्ठा होता रहता है, वैसे वैसे धार्मिक स्थान बड़ा होता रहता है। फिलहाल, बवाना जेजे कालोनी में 20 से ज्यादा छोटे-बड़े धार्मिक स्थल हैं, जिनमें से 10 से ज्यादा सरकारी जमीन (दिल्ली शहरी आवास बोर्ड, नगर निगम, डीडीए) पर अवैध रूप से बनाए गए हैं। बवाना जेजे कालोनी के बी, सी व डी ब्लाक में अभी भी धार्मिक स्थलों पर निर्माण जारी है।

पार्कों में धार्मिक स्थल बनाने का ही नतीजा है कि अब बवाना जेजे कालोनी के 80 फीसद बच्चे, युवा, बुजुर्ग व महिलाएं सड़कों पर खेलने व टहलने को मजबूर हैं। सुबह से शाम तक बवाना से नरेला रोड पर सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देते हैं।

स्थानीय निवासी संजय ने शुक्रवार को बताया कि जहाँ से बवाना जेजे कालोनी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का खेल चल रहा है। पहले छोटा सा धार्मिक स्थल बना दिया जाता है और फिर उसे बड़ा कर दिया जाता है। जब इस बारे में शिकायत की जाती है तो दिन के समय तो निर्माण कार्य रोक दिया जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में निर्माण कार्य जारी रहता है। उन्होंने बताया कि ब ब्लाक के धार्मिक स्थल का दरवाजा रातों रात में सड़क की तरफ बना दिया गया। अब इलाके के बच्चों के पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। बच्चे सड़कों पर खेलते हैं।

इलाके के विरेंद्र सिंह ने बताया कि बवाना जेजे कालोनी के हर पार्क पर अवैध रूप से धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके घर के बाहर भी एक धार्मिक स्थल बनाया जा रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अतिक्रमणकारी ने कहा, 'छोटे से धार्मिक स्थल से क्या अतिक्रमण होगा।' इसके बाद अब लोगों की धार्मिक भावनाएं धार्मिक स्थल से जुड़ गई हैं। साथ ही पड़ोस में कोई विवाद न हो, इसलिए वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं।

बवाना जेजे कालोनी सी ब्लाक के पार्क में अवैध रूप से बनाई जा रही मस्जिद। करीब 300 गज का यह पार्क डीडीए के अंतर्गत आता है • जागरण

बवाना जेजे कालोनी में मस्जिदों की स्थिति

ब्लाक	कुल मस्जिद	अवैध मस्जिद
ए	3	2
बी	5	1
सी	2	2
डी	2	2
ई	5	3
एफ	2	2
एम	1	1

सैकड़ों झुग्गियां बना रखी हैं सरकारी जमीन पर

सूत्रों के अनुसार बवाना जेजे कालोनी में सभी लोगों के घर हैं। लोग घरों को किराये पर देकर सरकारी जमीन पर झुग्गियां बनाकर रहते हैं। वर्तमान में बवाना जेजे कालोनी में सैकड़ों लोग झुग्गियों में रहते हैं। इन झुग्गियों में कई तरह के नशे की बिक्री भी खुलेआम होती है।

बवाना जेजे कालोनी के पार्कों में अवैध निर्माण की जानकारी प्राप्त हुई है। पता किया जाएगा कि नगर निगम की जगह पर अवैध निर्माण किया गया है या किसी दूसरे विभाग की। मामले की जांच कर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

रणजीत सिंह, निगम उपायुक्त, नगर निगम नरेला जोन

डीडीए को पर्यावरण मंत्रालय बताएगा राजधानी में कहां लगाने हैं पौधे

- पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नौ सदस्यीय समिति का किया गठन
- दस के स्थान पर दो पौधे लगाने के डीडीए के अनुरोध को किया खारिज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में पौधारोपण के लिए भूमि की कमी को दूर किया जाएगा। इसके लिए नौ सदस्यीय 'हरित आवरण विकास समिति' का गठन किया जा रहा है। यह समिति भूमि की कमी का विकल्प तलाशेगी। इसके साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उस अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया है, जिसमें भूमि की कमी की वजह से प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना के तहत दस के स्थान पर दो पौधे लगाने की अनुमति मांगी गई थी।

शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि डीडीए ने दिल्ली वन विभाग को पत्र लिखकर कहा कि विकास योजनाओं के लिए काटे जाने वाले वृक्षों की प्रतिपूर्ति के लिए पौधे लगाने को उनके पास भूमि नहीं है। ऐसे में दिशा-निर्देशों बदलाव किया जाए। लेकिन, पर्यावरण मंत्रालय ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया है। इसके बजाय डीडीए को यह बताया जाएगा कि राजधानी में पौधारोपण के लिए क्या विकल्प हैं। 'हरित आवरण विकास समिति' में लोक निर्माण विभाग, डीडीए, वन विभाग, नगर निगम, स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली शहरी कला आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-पूसा के सदस्य होंगे। यह समिति सरकारी भवनों की छतों पर उपलब्ध जगह, वर्टिकल ग्रीनिंग आदि जैसे विकल्पों पर भी गौर करेगी।

एफआरआइ से पौधारोपण का आडिट कराएगी दिल्ली सरकार : गोपाल राय ने कहा कि सरकार देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) से दिल्ली में पौधारोपण का तृतीय-पक्ष आडिट कराएगी। पिछले दो से तीन वर्ष में 27 एजेंसियों और विभागों को उनके विकास कार्यों के लिए पेड़ लगाने की अनुमति दी गई है। उनमें से प्रमुख रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल भूमि विकास प्राधिकरण और एमसीडी शामिल हैं। राय ने बताया कि विभागों से 13 मई तक प्रत्यारोपित किए गए पेड़ों की संख्या, उनके स्थान और उनके जीवित रहने की दर पर एक रिपोर्ट मांगी गई थी। इसमें विभागों ने बताया कि 55 प्रतिशत तक पेड़ परियोजना-वार जीवित रहने की दर है। हालांकि, कुछ एजेंसियों ने खराब प्रदर्शन किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: दैनिक जागरण | 5 --DATED-- नई दिल्ली, 14 मई, 2022

दिल्ली को तबाह कर रही भाजपा : सिसोदिया

अतिक्रमण विरोधी अभियान पर पार्टी विधायकों के साथ सीएम आज करेंगे बैठक

कुल ब्यूरो, नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) के सभी विधायकों के साथ अहम बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सिविल लाइंस स्थित केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर बैठक शुरू होगी जिसमें अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर भाजपा को राजनीति का मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी।

इससे पूर्व शुक्रवार को एक डिजिटल पत्रकार वार्ता में दिल्ली में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बुलडोजर से वसूली कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई को रुकवाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखा है। उनसे मांग की गई है कि मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर इस तरह की कार्रवाई को रुकवाया जाए।

सिसोदिया ने कहा है कि भाजपा ने नगर निगम के साथ मिलकर दिल्ली को तबाह करने की योजना बनाई है। इससे दिल्ली के 63 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली में 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। कच्ची कालोनियों और झुग्गियों में बने घरों में 60 लाख लोग रहते हैं। भाजपा को इन सब को तोड़ने की योजना है।

उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पहले नगर निगम अधिकारियों और भाजपा नेताओं की मिलीभगत से इसे अवैध रूप से बसाया गया। अब बुलडोजर चलाकर तोड़ा जा रहा है। साथ ही डीडीए कालोनी में बालकनी-छज्जा बनाने या घरों में छोटे-मोटे बदलाव करने वाले तीन लाख लोगों के मकानों को भी तोड़ने की तैयारी है।

गृह मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में यह सबसे बड़ी तबाही होगी। पत्र में उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर यह अवैध था तो भाजपा शासित निगम ने इसे बनने ही क्यों दिया? पहले 15 वर्ष तक अवैध निर्माण होने दिए गए। अब उन्हीं लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री से अपील करता हूं कि इसे समय रहते रोका जाए, नहीं तो दिल्ली में तबाही मच जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे नेता, विधायक और कार्यकर्ता आम जनता के साथ खड़े हैं। अगर हमें इसका विरोध करते हुए जेल जाने की जरूरत पड़ी, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे।

मीडिया को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया • डी. दिल्ली सरकार

- सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर चर्चा
- 63 लाख लोगों को बेघर करने की तैयारी, कार्रवाई रुकवाने को गृह मंत्री को लिखा पत्र

घर से अतिक्रमण हटाएं गुप्ता, वरना पहुंचेगा बुलडोजर : पाठक

आप आदमी पार्टी ने भाजपा शासित नगर निगम को चुनौती दी है कि यदि शनिवार सुबह 11 बजे तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर और दफ्तर से अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो आप कार्यकर्ता खुद बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में पार्टी की ओर से नगर निगम के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि आदेश गुप्ता के घर और दफ्तर में अवैध निर्माण किया गया है, लेकिन इस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। आप ने नगर निगम के मेयर और कमिश्नर को शिकायत लिखकर आदेश गुप्ता के घर और दफ्तर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। पाठक का कहना है कि पूरी दिल्ली को तबाह करने वाली भाजपा शासित नगर निगम के किसी नेता या किसी अधिकारी के खिलाफ अबतक बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई है?

पाठक को बुलडोजर चलाने का अधिकार किसने दिया : खुराना

वि., नई दिल्ली: प्रदेश भाजपा मीडिया रिलेशन विभाग के प्रभारी हरीश खुराना का कहना है कि यदि आप नेता कानून हाथ में लेने का दुस्साहस करेंगे तो कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि आखिर किस हैसियत से आप नेता दुर्गेश पाठक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। आखिर उनको किसने यह अधिकार दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, MAY 14, 2022

In sharp escalation, Sisodia shoots letter to Amit Shah over BJP's 'cheap bulldozer politics'

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 13

CALLING THE anti-encroachment drive by the MCDs "cheap and unjustified bulldozer politics", Deputy Chief Minister Manish Sisodia Friday wrote to Union Home Minister Amit Shah asking him to immediately stop the drive in Delhi.

"It is my appeal to you to ask your leaders not to do such dangerous politics in the name of bulldozer and demolition drive. Ask BJP leaders and MCD mayors, councillors and officials why they gave permission in the first place to construct houses in these areas. They first made a lot of money and are now displacing people under the pretext of bulldozer politics. Instead of creating trouble in the lives of people by demolishing their houses, action should be taken against such leaders and officials and a demolition drive should be carried out in the houses of leaders who gave permission to establish houses and societies in these colonies," he wrote.

Chief Minister Arvind Kejriwal has also called a meeting of all AAP MLAs on Saturday to discuss the issue. Officials said that a strategy will be chalked out to counter the BJP's politics over the anti-encroachment drives.

Deputy CM Sisodia

The demolition drives have taken a political hue ever since one was conducted in Jahangirpuri, days after communal violence erupted in the area. An outer gate of a mosque was among the structures taken down there, and the matter had reached the Supreme Court, which effectively stopped the MCD action by ordering status quo. While the BJP has sought to link such drives to "illegal Bangladeshis and Rohingya" living in the capital, the AAP alleges it is a bid by the civic bodies to extort money from people. Thursday was the first time residential buildings were demolished in Madanpur Khadar.

Addressing a press conference, Sisodia said, "Delhi has 1,750 unauthorised colonies where around 50 lakh people live, and around 10 lakh people live in 860 slum and JJ clusters. The Delhi BJP is planning to bulldoze all these houses and make people homeless. The leaders reach one colony every day with their bulldozers. This is cheap and unjustified politics."

He added that the AAP and every one of its leaders and party members will take to the roads to oppose this, and even go to jail to stop the demolition drive: "We will put our lives on the line, we will go to jail but we won't let BJP's terror prevail."

Sisodia also said notices have been issued to around 3 lakh residents living on authorised DDA land because they made minor modifications and extended their balcony or constructed a small structure on their terrace. "There is not a single house and bungalow where such small alterations have not been done," he said.

"This will result in India's worst calamity with more than 60 lakh people being homeless as a result of the BJP's bulldozer tactics in Delhi. There will be widespread outrage and there will be no greater damage in India's history," he said.

Hitting back at Sisodia, Delhi BJP president Adesh Gupta said the AAP leader was concerned over the demolition drive as bulldozers were being used to remove encroachments by Rohingya and Bangladeshis "given shelter" by his party.

In March, police declared AAP MLA 'bad character'

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MAY 13

AAP MLA Amanatullah Khan, arrested during protests against an MCD demolition drive Thursday, was declared a 'bad character (BC)' — a term typically used for persons with a criminal record — by the Delhi Police in March, The Indian Express has learnt.

Khan, the MLA from Okhla, was arrested after clashes broke out between locals and police personnel during an anti-encroachment drive by the South MCD in Madanpur Khadar. He was released on bail Saturday.

Khan's 'history sheet' was prepared by the SHO (Jamia Nagar) Satish Kumar on March 28, and approved by DCP (Southeast) Esha Pandey on March 30. It mentions details of 18 cases registered against him, of which he has been discharged in seven and acquitted in two. In one case the FIR was quashed, three of the cases were compounded, trial is pending in five.

Khan's lawyer, advocate Md Irshad, said: "They have declared him a 'bad character' just to defame him and tarnish the image of the Aam Aadmi Party. They have mentioned cases in which he has already been discharged or acquitted, or cases where trial/investigation is pending. We are going to the High Court against Delhi Police for defaming him."

The 'history sheet' prepared by SHO Kumar alleges: "Khan created terror in general. A total of 18 cases/FIRs have been registered against him in different police stations of Delhi. Most cases are related to intimidation, threatening, hurt, riots, causing hindrance duties of public servants and causing enmities between two groups/communities. In view of the above involvements of the proposed BC Amanatullah Khan, it is clear he has become a habitual and desperate criminal of the area. He has no respect for the law and has been repeatedly indulging in serious criminal activities."

"... Keeping in view his criminal record and activities, his surveillance is necessary. If approved, we may open his history sheet and his name be entered in register... so that a close surveillance on his activities can be kept," it alleges.

Will write to DDA on land for tree plantation: Rai

New Delhi: With DDA informing the Forest Department that land is scarce for tree plantation, the Delhi government will write to it seeking a report on land that is available, Environment Minister Gopal Rai said Friday.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI SATURDAY, MAY 14, 2022 DATED

₹15L And ₹10L To Kin Of 2 Who Died When Mountain Of Shame Crashed

Court Says The Deaths Appeared To Be Caused By Negligence Of Authorities

Usha.Das@timesgroup.com

New Delhi: Five years after two persons died when fifty tonnes of garbage crashed down the 16-storey-high mountain of waste in east Delhi's Ghazipur, a city court underlined it was "negligent conduct" of the municipal corporation and Delhi government in maintaining the landfill there that eventually caused the two deaths. On Friday, additional district judge Vijay Kumar Jha directed East Delhi Municipal Corporation and Delhi government to pay a compensation of Rs 15 lakh and Rs 10 lakh, respectively, to the families of Gautam and Kumari.

On September 1, 2017, after several days of rain, the garbage mound at the landfill had collapsed, in the process sweeping vehicles and seven people into the Kondli canal and causing the deaths of Abhishek Gautam and Raj Kumari.

Passing the order in both cases, the court said that "on the balance of probability", the two deaths appeared to have been "caused because of the negligent conduct of the defendants in maintaining the landfill".

A defence witness for EDMC had deposed that the garbage had collapsed due to technical and scientific reasons and it was a natural accident for which no person was responsible. To this, the court said that EDMC, by putting up such depositions, was trying to avoid the liability for the deaths on the ground and arguing that the landfill crash had occurred because of natural circumstances and that it was an act of god for which no person was responsible.

"The defendant no. 2 (EDMC) could have collected garbage at the landfill only up to 20-25 metres, whereas admittedly the height of the garbage was 60-65 metres. Whatever may be the explanation for this, it cannot be denied that if the permission was given to the defendant no. 2 to collect the garbage up to 20-25 metres, there must have been some reason for this and the logical reason appears to be that above that height to which the permission was granted to collect the garbage, it would be dangerous," the court observed.

The court noted that the defence witness had further stated that collection of garbage beyond the permitted capacity was due to compelling circumstances because an alternative site for disposal of the garbage despite many directions from different courts over 24 years hadn't been provided. If true, the court said, this reflected the "administrative apathy, making the officials and department concerned liable for any untoward incident" because of garbage being collected at the Ghazipur landfill beyond the permitted capacity.

File photo

On September 1, 2017, after several days of rain, the garbage mound at Ghazipur landfill had collapsed

EDMC HAD SAID

The garbage had collapsed due to technical and scientific reasons and it was a natural accident for which no person was responsible

Advocate Hitesh Bhardwaj, appearing for the two families, had sought compensation on the ground that the landfill hadn't been properly maintained by EDMC, resulting in the death of Gautam and Kumari.

With respect to the height of the mound, EDMC submitted that it had been demanding an alternative site from the landowning agency, Delhi Development Authority, for two decades to set up a waste management facility but none had been made available to the civic body despite various directions by the courts, forcing EDMC to continue dump daily waste at the Ghazipur landfill.

But the court stated that, even assuming that the incident September 2017 at the landfill occurred because of incessant rain for 2-4 days or due to natural or circumstantial reasons for which no person was responsible, the height of the garbage heap showed that it was not the "natural use of the land" at the landfill and this was proved by the loss of lives of the plaintiffs.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times DATED NEW DELHI SATURDAY MAY 14, 2022

Bulldozers will destroy Delhi: Sisodia in letter to Amit Shah

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi's ruling Aam Aadmi Party (AAP) escalated its confrontation with the Bharatiya Janata Party (BJP) over "bulldozer politics", with Delhi deputy chief minister Manish Sisodia urging the Union home minister Amit Shah to halt further demolitions in the Capital until investigations are carried out against functionaries of the civic bodies that are controlled by the latter's party.

The developements came a day after AAP legislator Amanatullah Khan was arrested by Delhi Police from southeast Delhi's Madanpur Khadar area, where protests broke out and locals clashed with police when civic officials attempted to bring down illegally built houses. Chief minister Arvind Kejriwal also called a meeting of all MLAs on Saturday to chart out a political counterstrategy.

In the letter, Sisodia said the civic bodies' demolition plans risked rendering homeless around five million residents of Delhi's 1,750-odd unauthorised colonies, and a million who live in 860 slum clusters.

"The BJP's plan in Delhi is now to run municipal bulldozers in all these colonies. Every day, BJP leaders reach some colonies with bulldozers. Not only this, the BJP has also handed notices to 300,000 residents of authorised DDA colonies and plan to carry out demolitions there as well, since people may have made minor alterations to their homes," Sisodia said.

"There will be hardly any flat or bungalow in Delhi where people have not got any minor alterations done," he added.

Home ministry officials did not respond to requests for comment.

Delhi BJP chief Adesh Gupta, in a statement, said the demolition action was being taken against encroachments "by Bangladeshis and Rohingya".

"These elements are involved in riots and criminal activities in the national capital and seek shelter under AAP leaders' protection. AAP is not bothered about the poor. Had it been bothered about them, the AAP government would have implemented central government's free health scheme (Ayushman Bharat) in Delhi. Had AAP been bothered about the poor, the Delhi government would have provided the homeless with homes. Only BJP cares about the poor," Gupta said.

At an anti-encroachment drive in west Delhi's Shyam Nagar. SANCHIT KHANNA/HT PHOTO

The controversy first began in the aftermath of the communal clashes in Jahangirpuri last month, where the North Delhi Municipal Corporation (North MCD) carried out an anti-encorachment days after communal riots broke out in the area between Hindu and Muslim groups. The Opposition, including the AAP and the Congress, accused the BJP of drawing from a playbook used in other BJP-ruled states where bulldozers targeted properties following communal clashes, or to target criminals from the minority community.

In recent days, the demolition drives in the Capital have snowballed – for most of the past week, however, they were peaceful except for protests that caused a drive to be aborted at Shaheen Bagh on Monday and led to protests at Madanpur Khadar on Thursday.

The BJP and the municipal corporations have denied allegations that the drives were targeted at particular communities.

The controversy has overshadowed what is a legitimate and a decades-long problem in the Capital, where swathes of settlements – in affluent as well as poor areas – are illegal, and temporary structures routinely pop up along key stretches, triggering traffic snarls and creating choke points.

Alleging that it was the municipal corporations, governed by the BJP for 17 years, that allowed unauthorised constructions to mushroom across the city, Sisodia said the saffron party was going to be "wiped clean" in the civic bodies and was intent on destroying peoples' homes on their way out.

"Before running bulldozers on the homes of the public, bulldozers should be run on the homes of those BJP leaders who allowed these constructions to be done by taking money and till the accountability is fixed and action is not taken against them, then the politics of this bulldozer should be stopped completely," he said.

Aam Aadmi Party (AAP) leader Durgesh Pathak, in a complaint to the South MCD mayor and commissioner, asked the civic body to investigate alleged illegalities during the construction of Delhi BJP chief Gupta's residence and office in West Patel Nagar.

He said "the AAP will bulldoze unauthorised constructions by Adesh Gupta" at his residence and office, if the MCD did not demolish them by 11am on Saturday".

"It has been weeks since the AAP exposed illegal constructions at Gupta's residence and office, but the MCD refuses to take any action," Pathak said. He claimed Gupta's office operates out of an MCD school – MCD Primary School, Diwan School (Opp. Block 28 & 32) in West Patel Nagar.

Hitting out at Pathak, Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor said, "If Durgesh Pathak or his party believe that there is encroachment outside Adesh Gupta's home, they should have complained to the MCD or approached the Lieutenant Governor or could have moved the court. But being anarchic by nature, the AAP leader [Pathak] has decided to take a bulldozer. They don't fear taking the law into their own hands."

BJP ASKS NORTH MCD TO RAZE 2 'ILLEGAL' ROOMS OUTSIDE AAP HQ

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Amid escalating war of words over anti-encroachment drives by the civic bodies, the Bharatiya Janata Party (BJP) on Friday demanded action against "illegal" constructions on the footpath outside the Aam Aadmi Party (AAP) headquarters at Rouse Avenue, Deen Dayal Upadhyay Marg.

In a letter to the North Delhi Municipal Commissioner Sanjay Goel on Friday, Delhi BJP spokesperson Praveen Shankar Kapoor claimed that there are two rooms constructed on the pavement outside AAP headquarters. Kapoor requested that an inspection of the area be carried out and the "illegal encroachment" be immediately demolished. "To our knowledge, these two rooms are under the occupation and use of the Aam Aadmi Party," wrote Kapoor.

While AAP did not respond to requests seeking a comment, senior party leader Durgesh Pathak earlier pointed to alleged illegalities in the construction of Delhi BJP chief Adesh Gupta's residence and office in West Patel Nagar, in a letter to the South MCD mayor and commissioner. Pathak gave the civic body time till 11am on Saturday to demolish the structures.

Hitting out at Pathak, Kapoor said, "Pathak is alleging that a single stair outside Gupta's residence, which is located in a congested area, is an encroachment. But he is silent on the two rooms outside his party's office."

BJP leaders said the AAP-led Punjab government too has taken action against encroachment. Harish Khurana, Delhi BJP media incharge, said, "In Punjab, Kejriwal justifies removal of illegal encroachments but in Delhi..., it is termed illegal."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times NEW DELHI SUNDAY MAY 15, 2022

Biggest blaze since 2019 puts fire safety rules back in focus

Paras Singh
letters@hindustantimes.com

People at the Sanjay Gandhi Hospital on Saturday, mourning the death of their loved ones. RAJ K RAJ/HT PHOTO, PTI & ANI

NEW DELHI: The tragic death of 27 people in a major fire in the Mundka building on Friday has underlined that the city authorities have learned little from similar incidents in the past that exposed the utter lack of safety mechanisms and the gaping holes in their implementation.

The Mundka building, according to an inquiry by the North MCD, had no sanctioned plan and was operating a factory without licence – same as the building in north Delhi's Anaj Mandi area where a fire in 2019 killed 43 people.

Hundreds of such buildings still operate from congested quarters with authorities struggling to curb them.

Two separate panels were formed after the Anaj Mandi fire to lay down an action plan to tackle the problem of illegal industrial activities going on from residential areas. The panels were formed after the National Human Rights Commission took suo motu cognizance of the matter.

The first one, a special task force, was formed by the ministry of housing and urban affairs. The second, an interdepartmental committee, was headed by the chief town planner of the South MCD. The panel submitted the action plan in 2020, and the STF gave its recommendations in 2021. Both have not been implemented yet, a senior official said.

A municipal official, who was part of the committee, said that the remedial action plan included the identification of vulnerable areas and formulation of detailed disaster management plans which were to be implemented in some areas, and then enforced in the entire city. "In residential areas with dense population, we suggested setting up fire hydrant systems with common water tanks, the alteration of road widths at key intersection points to allow movement of fire tenders, and the urgent tackling of unauthorised constructions," the official said, requesting anonymity.

Jai Prakash, former mayor of the north corporation, said despite several fire accidents in the city, there has been no action. "Making announcements about creating a world-class city should only take place after the agencies concerned have made the city a safer place for its residents," he added.

The Delhi Development Authority did not respond to queries on the implementation of the remedial action plan despite repeated attempts.

Meanwhile, an official from Delhi Fire Services, who asked not to be named, said that there are several areas in Delhi where even fire tenders cannot enter because of rampant unauthorised constructions. "Committees were formed after the Anaj Mandi and Arpit Palace Hotel fires, but nothing concrete happened," the official said.

To be sure, in case of the Anaj Mandi fire, the probe report for fixing culpability of officials was never made public.

In the aftermath of the Arpit Palace Hotel fire, a series of stricter norms was announced by the government on May 27, 2019. However, four months later, the Delhi government's urban development department issued an order to Delhi Fire Services and the civic bodies relaxing some of the norms based on representations of associations to the urban development minister. The September order undersigned by the deputy director (local bodies) said: "Instead of imposing the condition that fire safety certificate may be granted only if the floors above 3rd floor are closed/sealed by way of brick wall, we may instead obtain an affidavit from the hotel owners that such spaces will not be used for anything which violates any of the clauses stipulated earlier."

Delhi government spokespersons did not respond to requests seeking comment.

Praveen Khandelwal, general secretary of Confederation of All India Traders said that the city needs to take a holistic view of the industrial sector to prevent such fires. "Along the lines of regularising unauthorised colonies, a scheme can be brought out to incentivise structural and building norms corrections in such industrial units. In many cases, faulty electricity meters and wires cause short circuits and must be overhauled. In case of industries operating on narrow streets, authorities should relocate them in open areas," he added.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 15 मई 2022 DATED

साफ हुए तालाब में फिर छोड़ा जा रहा गंदा पानी

■ विस, द्वारका : लोगों ने जिस तालाब को सालों की मेहनत के बाद जिंदा किया था, अब उस तालाब में पिछले दो दिनों से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी अपना गंदा पानी छोड़ रही है। ऐसे में तालाब की देखभाल कर रहे लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की है। पुलिस अधिकारी के अनुसार उन्हें शिकायत मिल चुकी है, जांच की जा रही है।

कंस्ट्रक्शन कंपनी के गंदा पानी छोड़ने के खिलाफ एक्टिविस्टों ने दी पुलिस कंप्लेंट

लोगों ने सालों की मेहनत कर तालाब को फिर से साफ-सुथरा बनाया है

मामला द्वारका सेक्टर-23 के पार्क के तालाब से जुड़ा हुआ है। इस पार्क को रिवाइव करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एक्टिविस्ट दीवान सिंह के अनुसार द्वारका सेक्टर-22-23 के स्टॉर्म वॉटर ड्रेन में काफी गंदा पानी बहता है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने एक प्रोजेक्ट की सहूलियत को देखते हुए इस गंदे पानी को तालाब में छोड़ना शुरू कर दिया है। जबकि वह गंदा पानी आसानी से उसी ड्रेन में आगे की तरफ छोड़ने का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन कंपनी अपना खर्च बचाने के लिए इस तालाब के पानी में गंदगी मिला रही है।

लोगों के अनुसार 2012 से ही डीडीए के साथ स्थानीय लोग मिलकर इस तालाब को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। अहम बात यह है कि तालाब में मॉनसून का पानी भरा हुआ है। यानी यह तालाब प्राकृतिक है और पूरी तरह साफ पानी से भरा हुआ है। अब इसमें काफी संख्या में पक्षी और मछलियां भी हैं।

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MAY 15, 2022

Govt on the lookout for spots to develop food truck hubs

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: The Delhi government has started an exercise to identify land parcels in the city to develop food truck hubs. Joint teams of Delhi Tourism and Transportation Development Corporation (DTTDC) and land-owning agencies have started inspecting the land parcels under their jurisdiction where such markets could be established.

DTTDC, which has been assigned the responsibility to prepare a food truck policy and set up the hubs across the city, is likely to submit a report to the government next week.

According to officials, during his last meeting to review the progress made on various new schemes promised under the Rozgar Budget, deputy chief minister Manish Sisodia had asked the agencies to carry out a quick survey of the land parcels, examine the feasibility of setting up of food truck hubs and submit a detailed report within 10 working days.

The Delhi government has estimated that at least 15,000 new jobs will be created with the food truck business.

The representatives of various land-owning agencies had attended the meeting along with the officials of finance, planning, tourism and trade and taxes and gave brief presentation on their land clusters in the city.

Sources, however, said the government may not consider the land belonging to Delhi Development Authority and New Delhi Municipal Council, which are under the administrative control of the central government.

"Unlike Mumbai, which is a 24-hour city boasting of several locations that are thronged even after midnight, Delhi does not have that kind of concept. Also, the areas identified for the food truck hubs must be surrounded with habitat to ensure people can visit without any inconvenience," said a senior Delhi government official.

The food truck concept will not only create new job opportunities but is also expected to boost the national capital's nightlife. The hubs will operate between 8pm and 2am.

According to Sisodia, the food truck markets will play the role of a catalyst in providing a vibrant nightlife experience to the citizens of Delhi, on the lines of countries like the USA and Canada,

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS
। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 17 मई 2022 2

एमसीडी से इंडस्ट्री लगाने का लाइसेंस लेना नहीं है आसान

Sudama.Yadav@timesgroup.com

■ नई दिल्ली: दिल्ली के औद्योगिक इलाकों में अगर आप फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो एमसीडी से लाइसेंस लेना आसान नहीं है। कई महीनों के मशक्कत के बाद भी लोगों को लाइसेंस नहीं मिलता। नॉन-कन्फर्मिंग (लिलापशी) एरिया में खुले व्यापार फैक्ट्री ओनर्स के पास लाइसेंसिंग प्रक्रिया में जटिलताओं के चलते ही लाइसेंस नहीं है। फैक्ट्री या इंडस्ट्री खोलने के लिए भी अलग-अलग दो तरह के प्लॉट होते हैं। इसमें एक लीज होल्ड प्लॉट है जिसे डीडीए, डीएसआईआईडीसी या दिल्ली सरकार ने अलॉट किया है। दूसरा फ्री होल्ड प्लॉट, जिसका ओनर कोई शख्स खुद होता है।

दस्तावेजों की लिस्ट है लंबी, कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है मंजूरी के लिए

नोटिफाइड इंडस्ट्रियल इलाके में अगर किसी को इंडस्ट्री खोलनी है और प्लॉट डीडीए, डीएसआईआईडीसी या दिल्ली सरकार ने अलॉट किए हैं तो इसके लिए आवेदक को आवेदन के साथ डीडीए, डीएसआईआईडीसी या दिल्ली सरकार से प्लॉट अलॉटमेंट का लीज-डीड ओनरशिप कॉपी देनी होगी। इसके साथ सेक्शन बिल्डिंग प्लान, लेआउट प्लान, मशीनरी की डिटेल्स आदि भी देनी होंगी। इन डॉक्युमेंट्स के अलावा जिस जगह फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगानी है, वहां के साइट प्लान की कॉपी भी देनी होगी। सब कुछ साइट प्लान के अनुसार ही हो रहा है, इसके लिए नोटरी से सत्यापित शपथपत्र भी देना होगा। इसके अलावा जिस कंपनी एक्ट के तहत इंडस्ट्री खोली जा रही है, उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी चाहिए। फैक्ट्री लगाने वालों को अंडरटेकिंग भी देना होगा कि किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो उन पर एक्शन होगा और लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

एनवायरमेंटल कंसेंट व फायर NOC भी जरूरी

इतने सारे डॉक्युमेंट्स सबमिट करने के बाद भी अगर इंडस्ट्री खोलने का लाइसेंस मिल जाए, तो गनीमत है। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट से एनओसी और दिल्ली पल्यूशन कंट्रोल कमिटी (डीपीसीसी) से भी कंसेंट (मंजूरी) की कॉपी आवेदन के साथ लगानी होगी। तमाम डॉक्युमेंट्स पूरे होने के बाद एमसीडी का फैक्ट्री लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर मौके और एक-एक डॉक्युमेंट का सत्यापन करेगा। सारी चीजें पूरी होने के बाद 30 दिनों में लाइसेंस जारी किया जाता है।

दूसरी ओर, अगर किसी का अपना प्लॉट है, तो इसके लिए उसे लीज होल्ड की कॉपी के बदले कन्वेंस डीड की कॉपी लगानी होगी। बाकी प्रक्रिया व डॉक्युमेंट्स उसी तरह के होंगे। रिहायशी एरिया में फैक्ट्री खोलने के नियम-कायदे बिल्कुल ही अलग हैं। ऐसे इलाकों में कोई पल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्री नहीं खुल सकती। इसी तरह दिल्ली के 22 अनप्लांड इलाकों में फैक्ट्री खोलने के लिए नियम भी बिल्कुल जुदा हैं।

जलाशय भरे जाने का आरोप, HC ने मंगाईं तस्वीरें

■ प्रस, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने पश्चिमी जिले के मुंडका इलाके में मौजूद एक तालाब के संरक्षण की मांग से जुड़ी जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। याचिका में अवैध गतिविधियों के जरिए जलाशय को नष्ट किए जाने का आरोप लगाया गया है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने दिल्ली सरकार के अलावा डीडीए और स्थानीय पुलिस को भी याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता रौशन लाल को ऐसी तस्वीरें पेश करने का निर्देश दिया जो ये दिखाती हों कि तालाब का पानी सुखाकर उसे मिट्टी से भर दिया गया। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। इस दौरान जल बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश मिला है कि संबंधित जलाशय को नष्ट करने से जुड़ी कोई भी अवैध गतिविधि वहां पर न हो। डीजेबी को अगली सुनवाई पर इसकी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को देनी है।

Hindustan Times
NEW DELHI
SUNDAY
MAY 15, 2022

Building a firetrap, flouted an array of norms, say officials

Paras Singh
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: A preliminary inquiry by the North Delhi Municipal Corporation has shown that the Mundka building where a devastating blaze killed at least 27 people on Friday did not have a legal building plan, was operating a CCTV assembling unit without a factory licence, and lacked basic safety measures. The fire department has also confirmed that the building did not have a safety clearance certificate.

A senior North MCD official from the factory licensing department said that the preliminary inquiry has found that the building was located in the Lal Dora extension area of the Mundka village where industrial activity is not allowed.

"The unit did not have a valid factory licence or a DPCC (Delhi Pollution Control Committee) consent to operate. An application may have been filed by a unit in this property in 2014-15 but no licence was issued. This property lies in a non-conforming area [area where industrial activity was not allowed]," the official said.

The building — consisting of at least one assembly unit, commercial establishments and residential units — is located on a small plot on the border of Mundka industrial area and the village. The civic body is responsible for regulating operations in Lal Dora areas.

A senior official from Narela municipal zone, who is part of the inquiry team, said only trades, like grocery shops and salons, are allowed in Lal Dora extensions.

"Such a large assembly of people in the unit indicates that large-scale factory work was being carried out. We have also not found any records of the building plan of the plot so far," official said.

In the past, the municipal corporations of Delhi have submitted multiple affidavits promising to close industrial units in non-conforming areas of the city in the Supreme Court but the tragedy in Mundka has also raised questions about the efficacy of such drives.

According to officials, the North MCD issued orders on Friday to all six deputy commissioners to carry out surveys of such industrial units in their zones and take action against them in the next 10 days.

Anil Lakra, the local area councillor from AAP, said that action should be taken against guilty officials as well as owners.

Jogi Ram Jain, the standing committee chairman said that the inquiry report will be made public within three days. "Whatever fault is found on the MCDs' part, we will take action against the officials," he added.

AK Jain, former town planner and retired commissioner (planning), Delhi Development Authority, said there has been complete laxity in regulating lal dora areas. "DDA had suggested to the Delhi government that the list of all the factory units operating in such areas should be put in public domain so that people can check if a unit is operating legally. However, the suggestion wasn't accepted and the illegality continued," Jain said.

A municipal official said that the action against industries in non-conforming areas has been taken several times but new units keep opening up.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
NAME OF NEWSPAPERS नई दिल्ली, मंगलवार, 17 मई 2022 ---------DATED

बुलडोजर के विरोध में जेल जाने को तैयार रहें विधायक : केजरीवाल

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर अभियान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हम निगम की कार्रवाई के खिलाफ हैं। विधायकों से कहा गया है कि वे कार्रवाई के विरोध में जनता के साथ खड़े रहें। जरूरत पड़े तो जेल जाने के लिए भी तैयार रहें।

अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में केजरीवाल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह दिल्ली बसी है, उसमें 80 फीसदी हिस्सा अतिक्रमण के दायरे में आता है, तो क्या पूरी दिल्ली को तोड़ा जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो यह आजाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी अतिक्रमण के खिलाफ हैं। लेकिन जनता को बेघर कर सड़कों पर लाने से अतिक्रमण खत्म नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित निगम 63 लाख लोगों के घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। इनमें कच्ची कॉलोनियों में 50 लाख, झुग्गियों में 10 लाख और [illegible] की करीब तीन लाख संपत्तियों को तोड़ने की सूची बनाई गई है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि 'जहां झुग्गी, वहीं मकान' बना कर दिया जाएगा। लेकिन अब मकान तोड़ने में जुट गए हैं। केजरीवाल ने कहा, [illegible] निगमों को [illegible] है [illegible] निगम के [illegible] तोड़फोड़ के फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में तुरंत निगम चुनाव होने चाहिए। हम कच्ची कॉलोनियों को नियमित करेंगे।

› अवैध निर्माण कराया P 05

बिना कागज देखे कार्रवाई का आरोप

बैठक में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के नाम पर न तो कागज देखे जा रहे हैं और न लोगों को अपने कागज रखने का कोई मौका दिया जा रहा है। कहीं भी बुलडोजर चलाकर तोड़फोड़ की जा रही है। जो लोग पिछले 40 वर्षों से रह रहे हैं उनकी भी बिना कागज देखे उनकी संपत्ति तोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बिना नोटिस दिए किसी को बेघर नहीं कर सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर आप विधायकों के साथ बैठक की, निगम के चुनाव तुरंत कराने की मांग

भाजपा ने ही अवैध निर्माण कराए, अब बुलडोजर चला रही : सीएम

आरोप-प्रत्यारोप

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर सोमवार को आप विधायकों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल से निगम में काबिज भाजपा ने पहले पैसे लेकर अवैध अतिक्रमण कराए। अब इनका कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, तब पूरी दिल्ली में बुलडोजर चला रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। जहां-झुग्गी, वहीं मकान बना कर दिया जाएगा। भाजपा के लोग विधानसभा चुनाव नहीं जीते तो तोड़फोड़ शुरू कर दी। केजरीवाल ने कहा कि अब इनके पास नैतिक संवैधानिक [illegible] है कि इतना बड़ा निर्णय ले सकें। निगम चुनाव तुरंत होने चाहिए। चुनाव बाद जो नई एमसीडी बनेगी, वही इस तोड़फोड़ पर निर्णय ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से तोड़फोड़ शुरू हुई है, दिल्ली के लोगों में डर का माहौल है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आप विधायकों की बैठक ली। इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। • हिन्दुस्तान

केंद्र करे व्यवस्था

केजरीवाल ने बैठक के [illegible] करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को [illegible] कश्मीर में बसाने के लिए जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, वो करें। केजरीवाल ने कहा कि [illegible] के बाद से कश्मीरी पंडित [illegible] हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस राजनीति [illegible] नहीं [illegible] देश [illegible] है। अगर कश्मीर में रह रहे पंडितों को सुरक्षा नहीं मिल रही है तो देश के दूसरे हिस्से में रह रहे कश्मीरी पंडित, यह [illegible] लगेंगे।

'कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मिले, लाठियां नहीं'

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। कश्मीरी पंडितों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर लाठियां और आंसू गैस छोड़ने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को आलोचना की है।

केजरीवाल ने कहा कि राहुल भट्ट की हत्या से कश्मीरी पंडित गुस्से में और अपनी नाराजगी जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उनपर लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले छोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे वो कश्मीर में घर वापसी कर सकें। उन्होंने लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की।

कश्मीरी पंडितों को लेकर जारी बयान में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी। कुछ आतंकवादियों ने उनके कार्यालय में जाकर उनकी हत्या की। ऐसा लगता है कि [illegible] कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। हमारी सेना ने दोनों आतंकियों को [illegible] लेकिन इस [illegible] से चिंतित है कि कश्मीर में आज भी कश्मीरी पंडित सुरक्षित क्यों नहीं हैं। कश्मीरी पंडित वहां काम के [illegible] चाहते थे। कश्मीर [illegible] है।

कच्ची कॉलोनी पास करने की फाइल दबाई : गुप्ता

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा और निगम दिल्लीवासियों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी के झूठ को दिल्ली की जनता समझ चुकी है। दिल्ली सरकार ने [illegible] कच्ची कॉलोनी पक्की करने वाली फाइल दबा रखी है। निगम का बुलडोजर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर चलता है तो आप को परेशानी होती है।

आदेश गुप्ता ने कहा कि आप ने कच्ची कॉलोनी पक्की नहीं की। भाजपा दिल्ली की जनता के साथ है। आप यमुना की सफाई, [illegible] के मकान के नाम पर झूठ बोल रही है।

इधर, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि [illegible] पुनर्वास करने की बात करने वाली दिल्ली सरकार ने एक भी फ्लैट नहीं दिया है। [illegible] रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट में डाले गए और अब बुलडोजर चलने पर [illegible] हो रही है। इस सच को दिल्ली की जनता जान चुकी है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

* THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, MAY 17, 2022

NAME OF NEWSPAPERS ———————— DATED

A Month On, Road To Recovery Is Long & Arduous

JAHANGIRPURI: Residents Pick Up The Pieces After Communal Strife, Demolition Strike Dual Blow

Sakshi.Chand@timesgroup.com

New Delhi: It's a month since Jahangirpuri saw a tense day when communal passions threatened to spiral out of control. While the barricading and the presence of police and paramilitary personnel still remind of the violence that rocked the area on April 16, many other facets of life are back to normal. Movement of goods and services have mostly resumed and some of the structures demolished by North Delhi Municipal Corporation have been restored.

As a sign that things were returning to normal, Dilip Saxena reopened his juice shop a few days ago. A bulldozer had razed his shop at the Kushal Cinema intersection soon after the communal violence for allegedly encroaching on public land. "The corporation illegally demolished some structures and is now admitting they were wrong. But that won't compensate me for the loss I suffered," said Saxena. "Because of the sheer need to survive, I mustered whatever little I could and reopened my shop. But there are fewer people on this road now and business will take a while to pick up."

Shops like these were allotted to the residents by DDA in 1978 and the aggrieved owners claimed to have suffered even though they had valid licences to run them. Ganesh Gupta, who also has a juice shop close to Saxena's, worried that the setback will affect the wedding of his daughter in November. "The demolition squad broke my counter and damaged other things. The repair work requires money which I don't have and so I only open the shutters and sell soft drinks. I will have to request my daughter's prospective in-laws to change the wedding date," said Gupta.

Gupta disclosed that he had sued the municipal corporation for demolishing their shops without giving them notice. "In court, the corporation exhibited a fake notice. We never got them," he insisted. All the four roads at the Kushal Cinema intersection are open, but traffic is permitted only on a single carriageway, with the second carriageway occupied by the tents of the security personnel.

On Monday, TOI found Rihana Bibi, 41, frying pooris at her snack cart while her diabetic husband, Sheikh Sharat, was packing food for some customers. Bibi lost her food cart during the police action against rioters. Some do-gooders have helped her acquire another cart so she can start earning again.

"For almost a month, everyone here lived in fear," said Bibi. "We got a new cart, thanks to some good people, but it's still a struggle because we have to repay a loan of Rs 2 lakh. This, when cooking oil costs around Rs 180 a kilo and a gas cylinder over Rs 1,000. Earlier, I sold almost an entire pot of aloo-matar, but now cook less than half that."

The couple said that though the situation is better now, people still aren't out in numbers on the streets. But their business has also been hurt because they had to shift. Earlier, Rihana and Sharat stationed their food cart near the junction. But with the cops now stationed there, they have had to move from the lucrative area. "Once the policemen leave, I guess we will go back to that spot. We used to earn Rs 500-600 daily, but we barely get half that now," said Bibi.

Many food cart owners have had to shift from their earlier posts, even if temporarily. A prime location is outside the main mosque there, but security personnel are stationed there since April 16. Rahima's son, Asif, used to collect coins there with Mahatma Gandhi's picture and Mera Bharat Mahan inscribed on it but lost his piggy bank when their food cart was destroyed. Rahima has acquired a new one, but she hasn't resumed her business because the policemen now occupy the place where she stood her cart earlier.

Many others are similarly biding their time. Mohammad Fareed and his neighbours, Rashida and Rokiya, too had their food-cart business disrupted by the rioting and the police action. They said the money given as assistance by some people had gone into buying food for their families. Fareed said he was having a tough time paying the installments of a loan he had taken after his fried chicken snack cart was damaged and confiscated by the civic authorities.

Cops: Key accused financed violence, provoked people

Times News Network

New Delhi: Delhi Police's investigation in the Jahangirpuri rioting in April has determined that Mohammad Ansar was the chief financier for a group of individuals who had conspired to stoke violence on Hanuman Jayanti. Ansar's "core group" included two other accused, Tabrez and Enabul.

"Tabrez and Enabul were involved in provoking people during the riots. They also actively participated in the violence," a police officer disclosed. The duo, among others, received money from Ansar, he added.

Tabrez was one of the organisers of the Tiranga Yatra peace march conducted in Jahangirpuri on April 20 to send a message of communal harmony and peace in the area. He was a member of the peace committee and had also held a press conference with senior police officers requesting the maintenance of peace in the locality.

"Tabrez had political ambitions," the officer said. "We are now probing if he had a role in the anti-Citizenship (Amendment) Act protests." C Block and Kushal Chowk, where the violence of April 16 began, also figure prominently in the chargesheet filed by Delhi Police's Special Cell in the February 2020 communal riots case. Citing call intercepts, the chargesheet states that local residents were taken in buses to Maujpur and other areas for violence and arson under the guise of the anti-CAA protest.

The cops have recovered videos and documents that suggest the riots were pre-planned. Violence was provoked through messages and posts on a messaging platform. The cops are digging into the origins of these messages. The mobile phones of the accused have been sent for mobile forensics. "Examination of digital data captured by smartphones can provide significant and vital leads to the investigators," an officer explained.

The investigators believe the violence was planned for the afternoon during a Hanuman Jayanti procession. However, when that procession changed route at the last moment and did not pass through C Block, another procession was targeted. "Some recovered communication indicates a plan to disrupt the procession was in the works for two days," a police source said. The probe determined that stones, bricks and bottles were stored on rooftops a day before the incident.

A POLICE SOURCE SAYS

Some recovered communication indicates a plan to disrupt the procession was in the works for two days

The cops revealed that they are searching for seven to eight people who were actively involved in the violence and had fled the city after the riots. Police are carrying out raids Delhi-NCR and in some other states to nab the people suspected of being involved in the violence.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 17 मई ------DATED------

छिपे स्थानों पर पनप रहे हैं मच्छर, निगम ने शुरू किया अभियान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आखिर बरसात में ही अचानक मच्छर इतनी बड़ी संख्या में कहां से आ जाते हैं, जबकि गर्मी में तो ये सामान्यतः नजर नहीं आते। इसकी बड़ी वजह ऐसे स्थान होते हैं जो हमारी नजर से दूर होते हैं और वहां जमा पानी में मच्छर पनप रहे होते हैं। बढ़ते तापमान के चलते ये मच्छर बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात से मौसम ठंडा होना शुरू होता है तो ये मच्छर दूसरे स्थानों पर जाते हैं और जमा पानी में अंडे देते हैं। ऐसे ही स्थानों को खत्म करने के लिए दक्षिणी निगम ने विशेष मदर फोकाई खोज अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य छिपे हुए स्थानों पर मच्छर पनपने का केंद्र बने स्थलों को खत्म करना है।

दक्षिणी दिल्ली के डीडीए परिसर की पार्किंग में जमा पानी में मच्छरों के प्रजनन की जांच करते निगमकर्मी • सौजन्य : निगम

दक्षिणी निगम ने इस अभियान के तहत 168 निर्माण स्थलों और 25 सरकारी दफ्तरों को कार्रवाई के दायरे में लिया है। इनमें से दोषियों के विरुद्ध 106 कानूनी नोटिस एवं 77 अभियोजन दायर किए गए हैं। इनमें से 14 कानूनी नोटिस एवं आठ अभियोजन सरकारी विभागों को जारी किए गए। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निगम को ये स्थान 771 निर्माण स्थलों और 461 सरकारी दफ्तरों के निरीक्षण से मिले थे।

जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक दक्षिणी निगम क्षेत्र के दिल्ली जल बोर्ड के डियर पार्क स्थित बूस्टर पंपिंग स्टेशन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की सेवा नगर स्थित आईटीओ कंसल्टेशन की ओर से संचालित निर्माण स्थल, लाजपत नगर-4 स्थित राज कुमारी अमृत कौर कालेज, एनबीसीसी द्वारा संचालित डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज स्थित निर्माण स्थल, लोधी रोड डीटीसी बस डिपो, सनलाइट कालोनी पुलिस स्टेशन, सर्वोदय कन्या विद्यालय स्थित अनुज कुमार एंड लखनपाल, विकास स्थित नए स्टाफ क्वार्टर में मच्छरों के पनपने के स्थानों का पता चला है। इन निर्माण स्थलों पर मुख्य तौर पर भूमिगत टैंकों एवं ओवरहेड टैंकों में मच्छरों का प्रजनन पाया गया। इसके चलते निगम ने इन टैंकों को सफाई प्रति सप्ताह करने का निर्देश दिया है। इस वर्ष डेंगू के 82 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है।

कुम्हारों को मजबूत कर प्लास्टिक को किया जाएगा कमजोर

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प स्वरूप अब राजधानी में मिट्टी से बनी वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सोच के अनुरूप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर उपराज्यपाल अनिल बैजल के मार्गदर्शन में इस बाबत सभी संबंधित विभागों का एक समूह बनाया गया है। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जल्द ही इसका रोड मैप भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद मिट्टी से बने उत्पादों को रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं से बदला जाएगा।

- एकल प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए कुम्हारों को दिया जाएगा प्रोत्साहन
- मिट्टी से बने उत्पादों को रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं से बदलेंगे
- अमित शाह के निर्देश पर एलजी ने बनाया संबंधित विभागों का समूह, समय-समय पर की जाएगी समीक्षा
- देश में 65 लाख परिवार कुम्हारी कला पर हैं निर्भर, सुविधाओं के अभाव में कला हो रही है विलुप्त

जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने पांच मई को उपराज्यपाल बैजल के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि देश भर में 65 लाख परिवार आजीविका के लिए कुम्हारी कला पर निर्भर हैं, लेकिन कहीं मिट्टी न मिल पाने, कहीं भट्ठी न लगा पाने और कहीं उनके बनाए उत्पादों के लिए बाजार नहीं होने के चलते धीरे-धीरे यह कला विलुप्त हो रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री की अपील पर आधारित कुम्हार सशक्तीकरण योजना को प्रोत्साहित करने का प्रारूप तैयार करें। उपराज्यपाल ने कुम्हारी कला को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कमजोर करने के लिए भी एक जरिया बना लिया। उन्होंने इस पर दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से एक सर्वे रिपोर्ट बनवाई। पता चला कि दिल्ली में कुम्हारों के 1290 परिवार हैं। ये लोग मुख्य रूप से मिट्टी के मटके, कुल्हड़, गुल्लक, पानी की बोतल, तवा, सुराही, गमला, दीया और खिलौने बनाते हैं। यह सभी चीजें प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का विकल्प हो सकती हैं। इसके बाद नौ मई को बैजल ने दिल्ली के 12 प्रमुख कुम्हारों के साथ-साथ मुख्य सचिव नरेश कुमार, दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यावरण), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम, जल बोर्ड एवं दिल्ली विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें कुम्हारों की समस्याओं पर चर्चा करने के साथ-साथ उक्त सभी विभागों को सामंजस्य के साथ योजना का पूरा प्रारूप जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश दिया गया। उद्योग सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया।

दिल्ली में कहां कितने रहते हैं कुम्हार परिवार	
कालोनी	कुम्हार परिवार
प्रजापति कालोनी (उत्तम नगर)	490
विकास नगर कालोनी (उत्तम नगर)	550
कुम्हार बस्ती	50
दिल्ली के अन्य हिस्सों में	200

इस तरह सिरे चढ़ेगी सशक्तीकरण योजना

- खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक, पग मिल और इलेक्ट्रिक भट्ठी सब्सिडाइज्ड दरों पर मुहैया कराई जाएगी।
- हरियाणा से लाने के बजाय दिल्ली में ही भलस्वा झील और संजय झील से कुम्हारों को मुफ्त मिट्टी लेने की इजाजत दी जाएगी।
- मास्टर प्लान 2041 में घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हारी कला के लिए इलेक्ट्रिक भट्ठी के इस्तेमाल का प्रविधान किया जाएगा।
- कुम्हारों के बनाए उत्पाद दिल्ली हाट, फ्लाईओवरों के नीचे और बड़ी कार पार्किंग में भी शोकेस किए जाएंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER millenniumpost NEW DELHI | SATURDAY, 14 MAY, 2022 ---------DATED---------

Govt to form committee to examine land shortage for tree plantation: Minister Rai

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Environment Minister Gopal Rai on Friday said the city government will set up a nine-member committee to suggest alternatives to overcome the shortage of land for tree plantation in the national Capital.

The minister made the announcement while rejecting a request by the Delhi Development Authority to revise the compensatory plantation scheme guidelines and bring down the number of saplings to be planted for every tree felled from 10 to 2.

"The DDA wrote to the Delhi Forest Department saying they do not have land for compensatory plantation. They have requested us to make changes in the guidelines. We are rejecting the request considering the status of the environment in Delhi," he said. The government will instead ask the DDA to inform how much land is available for plantation in the capital, he said.

It has also been decided to set up a nine-member "Green Cover Development Committee" to suggest alternatives to overcome the shortage of land for tree plantations, Rai said.

The panel will have members from the Public Works Department, DDA, Forest Department, municipal corporations, School of Planning and Architecture, Central Public Works Department, Delhi Urban Arts Commission and the IARI-PUSA.

It will look at options like space available on the roofs of government buildings, vertical greening etc. Rai also said the government will ask the Dehradun-based Forest Research Institute to conduct a third-party audit of tree transplantation in Delhi.

"Over the last two to three years, 27 agencies and departments have been allowed to transplant trees for their developmental work. Prominent among them are National Highway Authority of India, National Capital Region Transport Corporation, National Buildings Construction Corporation, Delhi Metro, Delhi Jal Board, Public Works Department, Central Public Works Department, Rail Land Development Authority and MCD," he said.

"We had directed them to submit a report on the number of trees transplanted, their locations and their survival rate by May 13. A report suggests a project-wise survival rate of up to 55 per cent. However, some agencies have performed poorly," Rai said.

Based on the FRI audit report, the government will blacklist agencies and departments which have fared badly and review their permission for construction work, the minister said.

• 14 मई • 2022 | राष्ट्रीय सहारा

हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी करेगी कार्य

नई दिल्ली (एसएनबी)। राजधानी में वृक्षों के प्रत्यारोपण को सफल बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 9 सदस्यीय ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए काम करेगी। यह जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक के बाद दी। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि अब तक जहां-जहां वृक्षों का प्रत्यारोपण हुआ है, उसके ऑडिट की जिम्मेदारी देहरादून की ऑडिट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी गई है। पर्यावरण मंत्री बैठक में ऐसे विभागों के प्रति सख्त दिखे, जिन्होंने वृक्षों के प्रत्यारोपण को लेकर अभी तक सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। मंत्री ने ऐसे विभागों के सभी लंबित प्रस्ताव रोकने के निर्देश दिए हैं।

केजरीवाल सरकार ने 9 सदस्यीय ग्रीन कवर डेवलपमेंट कमेटी का किया गठन

बैठक में वन विभाग, नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन, सीपीडब्ल्यूडी, एनसीआरटीसी, पीजीसीआइएल, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे। बैठक में रिपोर्ट के अनुसार वृक्षों के प्रत्यारोपण की सर्वाइवल रेट औसतन 50 से 55 फीसद है। बैठक में कुछ एजेंसियों और विभागों के संतोषजनक परिणाम न होने के कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि वह प्रत्यारोपण को लेकर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून से ऑडिट कराएगी। अभी तक रिपोर्ट न सौंपने वाले विभागों एवं एजेंसियों के लंबित प्रस्ताव रोकने के साथ ही उन्हें काली सूची में भी डाला जाएगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि डीडीए ने जमीन की कमी को बताते हुए प्रस्ताव दिया है, कि काटे गए एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने की जगह केवल 2 पेड़ लगाने का निर्णय लिया जाए। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में भविष्य में होने वाली जमीन की कमी को ध्यान में रखते हुए, साथ ही हरित क्षेत्र को बढ़ाने को लेकर 9 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। कमेटी में पीडब्ल्यूडी के दो एवं सीपीडब्ल्यूडी, डीडीए, वन विभाग, नगर निगम, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, आईएआरआई (पूसा) का एक-एक प्रतिनिधि शामिल होगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF N अमर उजाला शनिवार, 14 मई 2022 ----DATED----

निगम की तैयारी 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की

सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया आरोप

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर भाजपा शासित तीनों नगर निगम के अतिक्रमण हटाने की आड़ में जल रहे विध्वंस अभियान को रोकने का आग्रह किया है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा के निर्देश पर तीनों निगम ने राजधानी में 63 लाख लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की है। उनका कच्ची कॉलोनियों और झुग्गियों में रह रहे 60 लाख लोगों के घरों को तोड़ने का प्लान है। इसके अलावा एक डीडीए कॉलोनी में बालकनी-छज्जा बनाने या घरों में छोटे-मोटे अल्टेरेशन करने वाले तीन लाख लोगों के मकानों को भी तोड़ेगी। इस तरह नगर निगम ने 70 प्रतिशत आबादी के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर करने का प्लान बनाया है। यह राजधानी में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अब तक की सबसे बड़ी तबाही होगी।

आदेश गुप्ता के घर व दफ्तर पर चले बुलडोजर : पाठक

आम आदमी पार्टी ने भाजपा शासित नगर निगम को चेतावनी दी है कि शनिवार सुबह 11 बजे तक प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर और दफ्तर में अवैध निर्माण को नहीं तोड़ने की स्थिति में वह बुलडोजर चलाकर उस पर कार्रवाई करेगी। आप नेता दुर्गेश पाठक ने दावा किया कि आदेश गुप्ता के घर और दफ्तर का निर्माण अवैध है। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

गृहमंत्री अमित शाह से अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने का आग्रह

विधायकों संग मुख्यमंत्री केजरीवाल आज करेंगे बैठक

नई दिल्ली। तीनों निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे बुलडोजर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मैदान में कूद पड़े हैं। वह अतिक्रमण विरोधी अभियान पर शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने पार्टी विधायकों को शनिवार सुबह 11 बजे सिविल लाइंस स्थित अपने निवास पर बुलाया है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर भाजपा की रणनीति का मुकाबला करने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। शेष

पौधरोपण के लिए भूमि की कमी की जांच के लिए बनेगी समिति

नई दिल्ली। राजधानी में पौधरोपण के लिए भूमि की कमी को दूर करने और विकल्प सुझाने के लिए समिति गठित की जाएगी। पैनल में लोक निर्माण

विभाग, डीडीए, वन विभाग, नगर निगम, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली शहरी कला आयोग और कृषि अनुसंधान संस्थान के सदस्य होंगे। इस संबंध में गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक की गई।

बैठक में वन विभाग, निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सीपीडब्ल्यूडी, एनसीआरटीसी, पीजीसीआईएल, पीडब्ल्यूडी व जल बोर्ड के अधिकारी शामिल रहे। गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में पौधरोपण के लिए भूमि की कमी को दूर करने के लिए विकल्प सुझाने के लिए सरकार नौ सदस्यीय समिति का गठन करेगी। उन्होंने यह घोषणा दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा प्रतिपूरक पौधरोपण योजना दिशानिर्देशों को संशोधित करने और हर पेड़ के लिए लगाए जाने वाले पौधों की संख्या को 10 से दो तक कम करने के अनुरोध को खारिज करते हुए की है। गोपाल राय ने कहा कि डीडीए ने दिल्ली वन विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि उनके पास प्रतिपूरक पौधरोपण के लिए जमीन नहीं है। शेष

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
SATURDAY, 14 MAY, 2022 | NEW DELHI

NAME OF NE... ----------DATED----------

Sisodia urges Shah to stop demolition drive in Delhi

Kejriwal calls meeting of AAP MLAs on Saturday

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has written to Union Home Minister Amit Shah urging him to stop the "destruction" ensuing in the national capital due to the anti-encroachment drive by the BJP-ruled municipal bodies.

Meanwhile, officials have said that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will hold a key meeting with all AAP MLAs on Saturday on the anti-encroachment drives. The meeting will begin at 11 am on Saturday at Kejriwal's official residence in Civil Lines.

In an online briefing, Sisodia slammed the "bulldozer politics" of the BJP and claimed that the civic bodies are planning to raze 63 lakh dwellings in the national capital.

"Of these, 60 lakh houses are in unauthorised colonies while the remaining three lakh are those where people have extended their balconies or covered them. We have learnt that notices have been sent to them," Sisodia said. "This will lead to a huge destruction in the national capital. Almost 70 per cent of the population of Delhi will be rendered homeless," he added. The Aam Aadmi Party will oppose the demolition drive and I have written to the Union home minister to seek his intervention in the matter, he said, adding that they are even ready to go to jail. Continued on P4

Sisodia urges Shah

"I have written to him (Shah) saying that this (demolition drive) should be stopped. If bulldozers are to be used, they should be used to demolish the houses of those BJP leaders and civic body representatives who took bribes to allow such structures to be constructed," he said.

In the letter, Sisodia said there are 1,750 unauthorised colonies where nearly 50 lakh people live and 860 slum clusters which are home to around 10 lakh people. "In Delhi, the BJP has a plan to run bulldozers on these colonies. Every day, some BJP leader reaches a colony with a bulldozer," Sisodia said in the letter written in Hindi.

"Apart from this, three lakh people residing in unauthorised and DDA colonies have been given notices for making alterations like extending their balcony or covering it. In reality, there is no house in Delhi where alterations have not been carried out," he added.

He further alleged that in the last 17 years, councillors, officials and mayors of the civic bodies took bribes to allow jhuggis and providing plots for unauthorised colonies.

Now when there is a threat to BJP's rule coming to an end in the municipal corporations, they are trying to ruin people's houses, he said.

"I appeal to you (Shah) to tell BJP leaders to not indulge in dangerous politics in the name of bulldozers and to fix accountability of those who let these illegal constructions happen," Sisodia said. Till accountability is fixed, there should be complete stoppage of "bulldozer politics", he added. An anti-encroachment drive in Delhi's Madanpur Khadar on Thursday sparked protests and pelting of stones where the locals claimed that legal structures were bulldozed.

AAP MLA Amanatullah Khan, who was a part of a protest in the southeast Delhi locality, was arrested on charges of rioting and obstructing public servants in discharge of their duty, police officials said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
NEW DELHI | SATURDAY | MAY 14, 2022

NAME OF N -DATED

Govt to form panel to overcome shortage of land for tree plantation, says Rai

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The Delhi Government has decided to set up a nine-member committee to suggest alternatives to overcome the shortage of land for tree plantation in the national Capital.

Delhi Environment Minister Gopal Rai on Friday made the announcement while rejecting a request by the Delhi Development Authority to revise the compensatory plantation scheme guidelines and bring down the number of saplings to be planted for every tree felled from 10 to 2.

"The DDA wrote to the Delhi Forest Department saying they do not have land for compensatory plantation. They have requested us to make changes in the guidelines. We are rejecting the request considering the status of the environment in Delhi," said the Minister.

"The Government will instead ask the DDA to inform how much land is available for plantation in the Capital. It has also been decided to set up a

nine-member 'Green Cover Development Committee' to suggest alternatives to overcome the shortage of land for tree plantations," said Rai.

The panel will have members from the Public Works Department, DDA, Forest Department, municipal corporations, School of Planning and Architecture, Central Public Works Department, Delhi Urban Arts Commission and the IARI-PUSA.

It will look at options like space available on the roofs of government buildings, vertical greening etc. Rai also said government will ask Dehradun-based Forest Research Institute to conduct a third-party audit of tree transplantation in Delhi. "Over last two to three years, 27 agencies and departments have been allowed to transplant trees for their developmental work.

Prominent among them are National Highway Authority of India, National Capital Region Transport Corporation, National Buildings Construction Corporation,' Delhi Metro, Delhi Jal Board, Public Works Department, Central Public Works Department, Rail Land Development Authority and MCD," said Rai.

"We had directed them to submit a report on the number of trees transplanted, their locations and their survival rate by May 13. A report suggests a project-wise survival rate of up to 55 per cent. However, some agencies have performed poorly," Rai said.

Based on FRI audit report, government will blacklist agencies and departments which have fared badly and review their permission for construction work, the minister said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU
SATURDAY, MAY 14, 2022 NEWSPAPERS DATED

INTERVIEW | SANTISHREE DHULIPUDI PANDIT

'I want to change JNU's image. It's a nationalistic university'

JNU V-C says it's extremely unfortunate that debate today is not intellectual but physical, which is not good for any varsity

JAIDEEP DEO BHANJ

Jawaharlal Nehru University Vice-Chancellor Santishree Dhulipudi Pandit, who took charge in February this year, says the university is not looking to start new schools but consolidate the strengths of the existing ones. Talking to The Hindu, she said the plans to start a medical college and hospital have been shelved and the university is making efforts to provide infrastructure to its School of Engineering and School of Management that were started without basic infrastructure. Excerpts:

It has been over three months since you returned to your alma mater as Vice-Chancellor. In what way do you think the university has changed? What needs to be changed?

■ It has been wonderful to come back to an institute that helped me grow. JNU gave me an all-India viewpoint when I came here from Tamil Nadu and it opened up the world to me. What has changed is that when I was a student, irrespective of what the major viewpoint was, the debate used to be very academic and constructive. It was in the form of speeches and pamphlets. There was no violence. I find it extremely unfortunate that the debate today is not intellectual and has become physical, which is not good for any university.

This entire debate questioning JNU's nationalism that has come up over the last six years has hurt me a lot because JNU is a nationalistic university.

I do not believe in representing any viewpoint. I believe that I represent JNU and all students here are equal. We can politically disagree and agree to disagree, but at the level of a human being we can still be very good friends. This is what JNU taught me during my student days.

Another thing that has changed is that back then when I was a student, JNU was not so crowded. We were only 3,000 students at that time and now we are 9,000-10,000 students. It has grown quite a bit, which has thrown up many challenges.

Do you think the university is facing an image crisis?

■ I want to change the image of JNU because what is being projected is not the reality. You can't judge a university from a 5% lunatic fringe. The majority of the students here have come from marginalised backgrounds looking to make a career, so this stereotyping hurts not only the university but the students as well. We are the topmost university not only in the country but also around the world in many fields. The perception is changing; people outside the university have understood that students of JNU don't only protest, throw stones, fight and raise anti-national slogans. We are a place for academics and research where there can be differences of opinion. I respect dissent, difference, diversity, democracy and development. An important message I want to give to all students is that we are all JNUites and we are human and should not spread hatred due to difference of opinion.

There is a need to revamp a lot of the infrastructure at the university, which is crumbling, as well as build hostels for the growing number of students. There are many green laws that do not permit construction on the campus. How is JNU trying to accommodate so many students?

■ We are not going to start any new schools or plan expansion during my tenure. During the last Vice-Chancellor's tenure, many new schools were started and we are now having issues because we opened them without having the infrastructure and the faculty. We need to first resolve those issues and consolidate ourselves. Even in areas where we were given the approval to build by the DDA in 2010, we have not been able to start projects and will start doing so soon. The Higher Education Financing Agency loan will help us build and we are bringing in private philanthropy to update our labs. We are also planning to redo our classrooms and bring in state-of-the-art hybrid classrooms where a teacher can teach an audience outside JNU as well. It will help us expand not on campus but reach out to rural India. For the classrooms as well, we are looking at private philanthropy. We have not received any contribution from our alumni yet to fund developmental projects and the funds we get from the Central government are limited.

> I do not believe in representing any viewpoint. I believe that I represent JNU and all students here are equal

JNU had announced a plan to start a 500-bed hospital and medical college. What is the status of that plan?

■ That plan has been shelved for now because we don't have the space and also it needs a lot of funding. Even the engineering and management schools have had a lot of teething problems. JNU is a brand name and I don't want to do anything just because it has to be done. Our management school needs to compete with an IIM and we need to have a faculty of the same calibre and offer students placements. Same is the case with the engineering school, we don't have a building, we don't have labs. It is criminal to start schools without facilities being in place first. We can't take differential fees from students and then offer them the same facilities as other students. If we cannot offer the students half of what IIT provides, we are failing the students. What has already begun, we can't close them down, so we are looking how to strengthen them.

What are the other growth plans?

■ Apart from IITs, JNU is the only other university for which there's a demand for offshore campuses. This shows that we are recognised all over the world. Many African nations have shown interest in JNU starting offshore campuses in the field of social sciences, international relations and languages. We are looking at how to consolidate our strengths and build on infrastructure, get better faculty and update our programmes. We are looking to offer joint degrees as the NEP has introduced the academic bank of credit. When it comes to international relations and languages, we have huge funding coming in from the European Union as well as Korea, Taiwan, Spain and Malaysia. We also want to be the digital hub of knowledge so we are strengthening our e-learning offerings.

First-year students, who are attending online classes, have been demanding immediate allotment of hostels. What steps are being taken to accommodate them?

■ UGC has been giving extensions to PhD students and around 200 PhD students from JNU have sent an appeal that they want extension. How can I then throw them out of hostels and allot rooms to new students. That will create another problem, so we are looking at ways to get the first-year students, who are online, back on campus. We only have two new hostels. One is Barak, which is for northeastern students that has been funded by the Ministry of northeast affairs that will be inaugurated in a month. The other is Shipra II, which will cater to the rising number of women students on campus.

Are there any plans to reinstate the Gender Sensitisation Committee Against Sexual Harassment (GSCASH), which was replaced by the Internal Complaints Committee? There has been a huge demand from students as they feel that the GSCASH was more effective.

We have to go as per the guidelines set by the UGC. But I agree there are many professors who are misogynistic and self-confessed molesters and they have to be brought to book as the student is always the victim as it is an unequal relationship. Any woman student who comes and complains has a lot of courage, so we are looking into how we can work on strengthening the redress mechanism. I would rather believe a student than a faculty because I don't think someone will come and lie on such an issue. I am trying to make people more sensitive, sympathetic and empathetic. I am also telling them that it is not only the girls who need to be counselled, the men have to be counselled. No faculty has been punished yet. I think if we punish one, it will send out a clear message that such behaviour won't be tolerated. We are also going to get a new security agency on campus, which will be more gender-sensitive.

DDA makes another attempt to revive interest in its land pooling policy

It will issue notices to form consortiums

MUNEEB KHAN
NEW DELHI

With an aim to boost interest in its land pooling policy, the Delhi Development Authority (DDA) is working on issuing conditional notices for the formation of consortiums of landowners this month, according to a senior official in the urban body.

Once a consortium in a particular sector comes into being, it will become the consortium's responsibility to convince the other landowners of that particular sector to pool in their land parcels, so that the minimum threshold of 70% contiguous land is reached and the sector becomes eligible to be taken over by authorities for development works.

Explaining the rationale behind this development, a senior DDA official said through the conditional notices the urban body now looks to shift the responsibility of achieving the minimum 70% contiguity through the landowners who have already expressed their interest in the policy. The official added that the process of preparing and issuing conditional notices will take two weeks.

"Though this, the DDA will facilitate the forming of consortiums. The onus of ensuring the contiguous land will now be on the people who have expressed their interest in the policy. They must ensure contiguity in land by convincing other people in their sectors who are yet to express their interest in pooling their land parcels," the DDA official added.

This development comes slightly over two months after Union Minister for Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri announced a two-pronged strategy aimed at expediting the execution of the land pooling policy.

One of them was amending the Delhi Development Act, 1957. The proposed amendment sought to make land pooling mandatory once the participation rate in a sector reaches the minimum threshold of 70%.

However, the proposed amendments were not introduced in the most recent Parliament session, which concluded in April.

The alternative plan was to issue conditional notices to landowners, who have already expressed their interest in the policy, to form consortiums – the plan which is now being put into action by the DDA.

While ambitious on paper, the land pooling policy has been a dead-end in terms of execution, with no development works taking place since it was notified – on two occasions, in 2013 and 2018.

To give an instance of the waning interest in the land pooling policy, sample this – only 19 applications and 12.6 additional hectares were registered during the last extension given by the DDA for land pooling applications – from January 24 to February 28. Since the agency first opened its window for land pooling applications in February 2019, a total area of 7,275.45 hectares from a total of 6,922 applications have been registered.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI NEWS 15 मई, 2022 DATED

मंदिर पुनर्विकास पर मंथन | नियुक्त प्रशासक की ओर से सबमिट की गई हाईकोर्ट में रिपोर्ट

कालकाजी मंदिर के पास बनीं 50 धर्मशालाओं को किया जाएगा ध्वस्त!

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट में कालकाजी मंदिर पुनर्विकास मामले में हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त प्रशासक ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट की अमलीजामा पहनाया गया तो मंदिर के आसपास बनी करीब 40 से 50 धर्मशालाओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इनकी जगह तिरुपति बालाजी की तर्ज पर वेटिंग रूम बनाए जा सकते हैं। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जस्टिस (रिटायर्ड) जे आर मिढा को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि मंदिर के आसपास ज्यादातर जमीन डीडीए की है। यहां तक की महंत जिस जमीन पर बैठे हैं, वो भी डीडीए की है। मिढा ने कहा है कि आर्थिक अपराध शाखा ने पहले कभी इस मुद्दे पर लैंड ग्रैबिंग का मामला दर्ज किया था। लेकिन हैरानी की बात है कि डीडीए की जमीन और उसकी ओर से कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासक ने हाईकोर्ट को सुझाव दिया कि मंदिर के आसपास 40 से 50 धर्मशालाएं हैं। इन्हें तोड़कर वहां पर तिरुपति बालाजी की तर्ज पर

वेटिंग रूम बनाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ लगती है।

रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार और शनिवार को यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 30 से 40 हजार रहती है। वहीं नवरात्र के दौरान यह संख्या 1 लाख के पास रहती है। लिहाजा जो भी योजना बने वह वहां आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर बने। प्रशासक के अनुसार धर्मशालाओं को तोड़कर वहां वेटिंग रूम बनाना ही सही होगा। जहां पीने के पानी से लेकर शौचालय आदि तक की सुविधा होनी चाहिए। प्रशासक की ओर से रिपोर्ट में कहा गया कि इस मंदिर में 700 के करीब पुजारी हैं। उनमें से मुट्ठीभर लोग ही हैं जो धर्मशालाओं को तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने मामले में कहा कि बारीदार और पुजारी अगर पुनर्विकास के लिए रास्ता देते हैं तो उन्हें सुना जाएगा और इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जबकि पिछली सुनवाई में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने मंदिर परिसर में अवैध निर्माण रोकने के लिए और जमीन की सुरक्षा को चारों ओर बैरीकेट्स लगाने या चारदीवारी करने के निर्देश दिए थे। बेंच ने कहा था कि हर रोज अतिक्रमण होता रहा तो मंदिर के पुनर्विकास की पूरी प्रक्रिया खतरे में पड़ जाएगी। बेंच कालकाजी मंदिर के रखरखाव और पुनर्विकास के पहलू से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। बेंच ने जमीन की सुरक्षा के काम को लेकर संबंधित तहसीलदार, राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी और डीडीए अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए। जबकि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कालकाजी मंदिर कोष से आर्किटेक्ट को 10 लाख रुपए जारी करने के निर्देश दिए थे।

दिल्ली पुलिस ने एसएचओ कालकाजी के माध्यम से बेंच को यह भी आश्वासन दिया था कि धातु की चादरों या किसी अन्य प्रकार के बैरीकेट्स के माध्यम से बनाई गई चारदीवारी की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कालकाजी मंदिर में कोई अनधिकृत कब्जा या अतिक्रमण न हो। और बेंच ने एसडीएमसी और दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिए थे कि वे रेहड़ी-पटरी वालों को मंदिर की परिधि में फेरी लगाने के लिए कोई अनुमति न दें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPA राष्ट्रीय सहारा 16 मई • 2022 ------DATED--------------------

डीडीए कॉलोनियों में हो रहा अतिक्रमण

मयूर विहार फेज-1, पूर्वी दिल्ली डीडीए फ्लैट कालोनी बसे हुए लगभग चार दशक हो गए। डीडीए द्वारा अलॉटमेंट के समय जनता को जो फ्लैट आवंटित हुए थे, आज उन फ्लैटों के आगे अत्यधिक अतिक्रमण हो चुका है। स्थिति ये है कि ऊपर के फ्लैटों में रहने वालों को गाड़ियां पार्क करने की जगह भी नहीं मिलती, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर मालिकों ने सड़कों को 5 से 10 फिट आगे तक गेट लगा कर सड़क पर कब्जा जमा लिया है और उससे आगे अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया जाता है। इसके कारण अन्य लोग परेशान होते हैं, लेकिन प्रशासन के पास अतिक्रमण से निजात के लिए समय ही नहीं है। अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अतिक्रमण से जनता को निजात दिलाएं।

स्थानीय निवासी, पॉकेट चार, फेज वन मयूर विहार।

खुलेआम बेचे जा रहे मादक पदार्थ

कापसहेड़ा में राधेश्याम मंदिर वाली गली में रोजाना मादक पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं। पूरा दिन गली में असामाजिक तत्वों का जमघट लगने के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। असामाजिक तत्वों को किसी का डर नहीं। समझ में नहीं आता कि स्थानीय पुलिस बीट ऑफिसर यहां गश्त क्यों नहीं करते, क्या उनको इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं। इस तरह की अवांछित गतिविधियों से इस गली के लोग बहुत डरे हुए हैं, उनके साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। इस गली में रहने वाले शाम होते ही गली में बाहर जाने से डरने लगे हैं। हम गलीवासियों का पुलिस आयुक्त व दिल्ली पुलिस से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि यहां चल रहे नशे के गोरखधंधे को जल्द से जल्द बंद कराकर यहां के निवासियों को सुरक्षा प्रदान करें।

कापसहेड़ा के दुःखी निवासी।

आवेदन के बाद भी नहीं आई आईजीएल पाइपलाइन

गांव कापसहेड़ा में आज तक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है। वर्ष 2018-2019 में साईं कुंज व आशियाना अपार्टमेंट्स से घर-घर फॉर्म भी भरवा लिए गए। साथ में निर्धारित राशि के चेक भी लिए गए, लेकिन आज तक मटके वाली गली में पाइपलाइन नहीं आई। ऐसे में कनेक्शन का सवाल ही नहीं है। मेरा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के उच्चाधिकारियों से अनुरोध है कि इस काम को और लम्बित न करें और जल्द से जल्द पूरा करवा कर जनता को राहत प्रदान करें।

नरेंद्र जैसवाल, कापसहेड़ा।

लोकमंच

सार्वजनिक शौचालय की हालत खस्ता

राजधानी में सार्वजनिक शौचालयों की हालत खस्ता है। उसमें न पानी है न ही इनकी देखरेख की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय, रोहिणी, आजादपुर बस टर्मिनल और मोरी गेट अंतरराष्ट्रीय बस अड्डे पर स्थिति अधिक चिंताजनक है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन मॉडल टाउन बवाना नरेला आदि क्षेत्रों में दिल्ली नगर निगम के द्वारा सार्वजनिक शौचालयों को बनाया गया है। इसकी देखरेख न होने के कारण इनकी हालत खस्ता है। इनमें न तो पानी आता है न ही साफ-सफाई होती है। सभी उपकरण टूटे हुए हैं। देखरेख की जिम्मेदारी वाला विभाग पल्ला झाड़ रहा है। आम जनता को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों आदि को विशेष परेशानी होती है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से अनुरोध है कि व्यवस्था में सुधार कर लोगों को होने वाली परेशानियों से मुक्ति दिलाएं।

विजय कुमार धनिया सिरसपुर।

विकास मार्ग पर लगने वाला बना मुसीबत

लक्ष्मी नगर पुश्ता मार्ग से निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन (लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी) तक सुबह से रात 10 बजे तक लम्बा जाम लगा रहता है। विकास मार्ग नाम की इस सड़क की चौड़ाई कम होने और सड़क किनारे वाहनों द्वारा अतिक्रमण होने के कारण प्रीत विहार की तरफ जाने वाली सड़क पर यातायात रेंगता हुआ चलता है। लक्ष्मी नगर लालत बत्ती से निर्माण विहार पहुंचने में लगभग आधे घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। इससे वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण और एसी की गर्मी से पर्यावरण भी खराब होता है। ऐसे जाम लगने वाले क्षेत्रों में अगर कोई आगजनी या हादसा हो जाए तो दमकल विभाग और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं समय पर उपलब्ध नहीं हो सकती। पीडब्ल्यूडी द्वारा विकास मार्ग के दोनों तरफ की सड़कों और पटरियों को ये कह कर तोड़ दिया था कि यहां दिल्ली सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण होना है। लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रशासन और दिल्ली सरकार की आंखें नहीं खुल रही। दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि समस्या का शीघ्र समाधान करें।

प्रवीण कालड़ा, लक्ष्मी नगर।